बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 185

हरसंभव कोशिश

पुराने सारे जतन नाकाम होने के बाद गिरती आर्थिक वृद्धि दर को थामने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी ओर से सर्वस्व झोंक दिया है। गत तिमाही में आधिकारिक वृद्धि दर 5 फीसदी पर आ गई और मौजूदा तिमाही के बारे में पर्यवेक्षकों का कहना है कि इसमें और कमी आएगी। ऐसे में कॉर्पोरेट कर दर को घटाकर 25 फीसदी करके वित्त मंत्री ने वह कर दिखाया है जिसका वादा उनके पूर्ववर्ती मंत्री ने पांच वर्ष पहले किया था। उससे भी पहले इस बारे में प्रत्यक्ष कर संहिता का मसौदा भी पेश किया गया था। ऐसा करके वह कॉर्पोरेट कर दर को क्षेत्र के अन्य देशों के करीब ले आई हैं। यह कदम एक और अनुशंसा सामने लाता है और वह यह कि सरकारी व्यय में इजाफे की प्रतीक्षा के स्थान पर पैसे को निजी कारोबारियों के हाथ में जाने देना चाहिए।

घोषणा का चतुराईपूर्ण हिस्सा है नए निवेश के लिए 15 फीसदी की रियायती कर दर की घोषणा। यह काफी कुछ थाईलैंड की गत सप्ताह की घोषणा जैसा है। उसने चीन से थाईलैंड स्थानांतरित होने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर दर में 50 फीसदी कटौती करने की घोषणा की। वियतनाम भी लक्षित कंपनियों के लिए कम कर दर की पेशकश करता है। स्पष्ट है कि यह रियायती व्यवस्था यह देखने के लिए की गई है कि भारत को अमेरिका और चीन की कारोबारी जंग से लाभ होता है या नहीं। इसके साथ ही ठहरे हुए मेक इन इंडिया अभियान को गति देना भी इसका उद्देश्य है।

क्या यह कारगर साबित होगा? इस पर चर्चा जारी है और इस बात पर आम सहमति है कि अर्थव्यवस्था मांग की कमी से दो चार है। ऐसे में कर पश्चात कॉर्पोरेट मुनाफे में बढ़ोतरी इस मसले को सतही ढंग से ही छूती है। मांग में पर्याप्त बढ़ोतरी के लिए कंपनियों को भारी भरकम लाभांश भुगतान करने की आवश्यकता है। उन्हें ऐसी नई क्षमताओं में भी निवेश करना होगा जो वे अन्यथा नहीं करतीं। इससे पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जबकि अभी इसमें कमी आई है। कमजोर ग्रामीण मांग की समस्या इससे हल नहीं होती। न ही इस नई घोषणा से उन कंपनियों को मदद मिलती है जो मांग में कमी या निर्यात में गिरावट के कारण घाटे में हैं। केवल कर कटौती की घोषणा नहीं की गई है। ऋण मेले की पुरानी गलत आदत की भी वापसी हुई है। वहीं सरकारी बैंकों के लिए भी नया निर्देश है कि छोटे या मझोले उपक्रमों के किसी भी ऋण को वित्त वर्ष की समाप्ति तक फंसा कर्ज न घोषित किया जाए।

राजकोषीय संयम को पहले ही तिलांजलि दी जा चुकी है। कर राजस्व पहले ही लक्ष्य से पीछे चल रहा है। घाटे के अघोषित हिस्से (सरकारी कंपनियों के बहीखाते, सरकार के बकाया बिल आदि) के साथ इस वर्ष का घाटा एक दशक के उच्चतम स्तर पर हो सकता है। इससे पहले वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान वर्ष 2009-10 में यह 6.4 फीसदी रहा था।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

ध्यान रहे कि वित्त मंत्री के संवाददाता सम्मेलन से एक दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर ने घोषणा की थी कि राजकोषीय प्रोत्साहन की गुंजाइश बहुत कम है। पूर्ववर्ती गवर्नर भी ऐसा कह चुके हैं। ऐसा प्रोत्साहन जो सरकार के बड़ी उधारी के कार्यक्रम में तब्दील हो सकता है, उसकी घोषणा कर वित्त मंत्री ने ऋण बाजार का गणित बदल दिया है और आरबीआई द्वारा अगले महीने अनुमानित नीतिगत दर कटौती को भी दिक्कतदेह बना दिया है। इसके अलावा फिलहाल मुद्रा बाजार की जो स्थिति है उसमें दरों की कटौती पूरी तरह परिलक्षित भी नहीं होगी। ऐसे में शेयर बाजार तो जश्न मना रहा है लेकिन ऋण बाजार के लिए समस्या खड़ी हो गई है। अर्थव्यवस्था में हर चीज की कीमत होती है।

कर दरों में कटौती इस तरह की गई है कि यह राज्यों को गहरे तक प्रभावित करती है। इसलिए क्योंकि यह कटौती बुनियादी कर में की गई है जिसका राजस्व राज्यों के साथ साझा किया जाता है। यदि कटौती अधिभार में होती तो पूरा बोझ केंद्र पर पड़ता। सहकारी संघवाद का वादा करने वाली केंद्र सरकार के समक्ष राज्यों की एक और शिकायत होगी। इससे पहले केंद्र ने वित्त आयोग की शर्तों को नए तरीके से तैयार किया था जिसके तहत केंद्र के राजस्व का एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा करने के पहले ही खाली होना है। इतना ही नहीं आक्रामक रुख अपनाते हुए उसने प्रस्ताव रखा है कि आयोग केंद्रीय कर में राज्यों की हिस्सेदारी को मौजूदा स्तर से कम किया जाए। इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया इसलिए केंद्र और राज्यों के राजकोषीय संबंध में भी तनाव है। बहरहाल, कंपनियां और निवेशक खुश हैं तो दिक्कत ही क्या है?

अजय मोहंती

एल्गोरिद्म के प्रबंधन से बनेगा सूचना युग का ढांचा

सूचना युग की तरफ बढ़ते कदम एल्गोरिद्म से जुड़ी चुनौतियां भी लेकर आ रहे हैं। इससे रोजगार का स्वरूप एवं आकार भी बदलेगा। इस पहलू पर रोशनी डाल रहे हैं **अजित बालकृष्णन**

अपने मोबाइल फोन पर दिन भर आने वाले संदेशों को देखते रहना, अपने फोन पर अपनी पसंद के हिसाब से फिल्में देखना, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद के सामान खरीदने जैसे मजेदार कामों के अधिक गहरे मायने भी हैं। यह सूचना युग की दस्तक को बयां करता है। सूचना युग अब महज बेकार की बौद्धिक चर्चा भर नहीं है, हम इस युग में धीरे-धीरे घुसते जा रहे हैं। खास बात यह है कि हम सूचना युग से जुड़े पहलुओं को पूरी तरह समझे बगैर ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में सूचना युग की तरफ हमारा पारगमन उस समय हो रहा है जब दूसरे तमाम बदलाव भी घटित हो रहे है

मसलन, करोड़ों भारतीय इस समय जिस बदलाव से गुजर रहे हैं वह कम प्रतिफल देने वाली पारिवारिक खेती से हटकर एक तय वेतन के साथ अधिक अनुमेय जीवन की तरफ जाता है। इस बदलाव की तरफ कदम बढ़ाने का तरीका यह है कि आप एक ट्रेन में सवार होकर मुंबई या किसी भी नजदीकी महानगर की ओर कूच कर जाइए। भले ही वहां पर आपको झुग्गी-झोपड़ी में ही क्यों न रहना पड़े और आपकी पत्नी को किसी घर में जाकर शौचालय साफ करना पड़े, लेकिन वहां पर किसी दुकान में सहायक का काम करने पर भी मिलने वाला मासिक वेतन कम होने पर भी आपको थोड़ा सुकून देगा। यह गांव में रहते हुए दिनभर अपनी गायों की देखभाल करने में लगा देने से कहीं बेहतर अहसास देता है। आखिर कोई ग्रामीण गाय इसी उम्मीद में पालता है कि उसके दूध को वह वाजिब कीमत पर बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। शहर की झुग्गी बस्ती के अपने ठिकाने पर शराब का तीसरा गिलास पीने के साथ ही आप पर यह अहसास हावी होने लगता है कि गांव में सरपंच रहे दादा को ऐसी जिंदगी देखकर कैसा लगता? लेकिन शराब का नशा हावी होते ही यह अहसास गायब हो जाता है और उस झुग्गी की जिंदगी ही खुशी देने लगती है।

इसी तरह करोड़ों भारतीय ऐसे भी हैं जो गांव में अपने पुश्तैनी दुकान पर बैठने के बजाय किसी कंपनी में सेल्समैन का काम करते हुए वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित रोजगार को तरजीह दे रहे हैं। यह अलग बात है कि सेल्समैन के तौर पर उन्हें घर-घर जाकर दरवाजा खटखटाना होता है और अक्सर उन्हें बुरा-भला भी सुनना पड़ता है। एक सामान बेचने के लिए उन्हें दरवाजों के चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन उन्हें इस बात का सुकून होता है कि महीना खत्म होने पर उनके खाते में एक तय रकम आ जाएगी।

ऐसा ही एक बदलाव गांव में पूजा-पाठ करते हुए आजीविका कमाने वाले अपने पिता के उलट शहर में आकर किसी कंपनी में अकाउंटेंट बनने का भी घटित हो रहा है। शहर में उस युवक को इतना वेतन तो मिल ही जाता है कि वह कुछ रुपये अपने बूढ़े होते मां-बाप के लिए भी अपने गांव भेज सके।

भारत भले ही इन तमाम बदलावों से गुजर रहा है लेकिन इसी के साथ एक और तरह का बदलाव भी दस्तक दे रहा है। मसलन, हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें क्लर्क एवं सेल्समैन की अधिकता वाली अर्थव्यवस्था की जगह तकनीकी निगरानी वाली मानव की भूमिका हावी होने वाली है। यह भूमिका आंकड़ों के आधार पर नतीजे निकालने वाली 'एल्गोरिद्म' को संभालने की है। यह काम भेड़ों या गायों की देखरेख करने या किराने की दुकान संभालने से बहुत अलग नहीं है। गाय और भेड़ें जिस तरह घास के मैदानों में घूमती रहती हैं उसी तरह एल्गोरिद्म भी डेटा के मैदान में विचरण करता है।

लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह खेतों में गाय चराने के लिए आपको पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, उसी तरह एल्गोरिद्म के लिए भी आपको कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आपको एल्गोरिद्म का कामकाज देखने के लिए भी कुछ उन्हीं वजहों से नौकरी मिलती है जिस वजह से गाय चराने का काम मिलता है: यानी कोई दुष्ट आपकी गाय या एल्गोरिद्म को चुरा सकता है, आपकी गाय या एल्गोरिद्म दूसरे के इलाके में जा सकता है और कुछ वर्जित चीजें ग्रहण कर सकता है। संभावित ग्राहक के सामने क्या उत्पाद परोसे जाएं, चैटबोट अवतार में उस ग्राहक से सौम्य लहजे में आकर्षक बातचीत की जाए और बिक्री एवं पैसे जुटाने का काम अंजाम देने में भी एल्गोरिद्म ही तय करेगा। कोई भी इंसानी सेल्समैन इस एल्गोरिद्म सेल्समैन की बराबरी नहीं कर सकता है। लिहाजा बिक्री से जुड़ी नौकरियां गायब हो जाएंगी लेकिन एल्गोरिद्म के संचालन के लिए भी इंसानों की जरूरत बनी रहेगी।

इसी तरह दिनभर दफ्तरों में एक जगह से दूसरी जगह सामान इन-आउट करने में लगे करोड़ों लोगों की नौकरी भी एक एल्गोरिद्म के हवाले हो सकती है। लेकिन इस एल्गोरिद्म को भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमने पहले भी ऐसे बदलावों का बखूबी सामना किया है। आखिरकार, संस्कृत श्लोकों का पाठ करते हुए आजीविका कमाने से किसी दफ्तर में कागजी काम करने तक का सफर तय करने में आधी सदी लग गई थी। उसी तरह दाल-चावल खरीदने- बेचने वाले से म्युचुअल फंड एवं फिक्स्ड डिपॉजिट बेचने-खरीदने वाला बनने में भी आधी सदी गुजर गई। सवाल यह है कि म्युचुअल फंड या एफडी बेचने की आपकी जिस काबिलियत की तारीफ आपका बॉस भी करता है, उसकी जगह म्युचुअल फंड की खरीद-बिक्री करने वाले एल्गोरिद्म का संचालन करने वाली काबिलियत कैसे पैदा की जाए?

अब भारत के स्कूली बच्चों को ऐसी तालीम देने की जरूरत है कि 12वीं क्लास पूरा करते समय वे एल्गोरिद्म की दुनिया में किसी न किसी पहलू में पारंगत हो चुके हों। या तो वे एल्गोरिद्म का निर्माण करें या खंडित एल्गोरिद्म की मरम्मत करें या काम पर एल्गोरिद्म का निरीक्षण कर सकें।

अपने गृहनगर कन्नूर की अपनी सालाना यात्रा पर आने के बाद मुझे यह सवाल काफी परेशान कर रहा है। समुद्र के किनारे मैं लगभग उसी जगह पर बैठा हूं जहां पर वर्ष 1498 में वास्को डि गामा उतरा था। क्या उस समय उस जगह मौजूद रहे किसी भी शख्स ने कल्पना भी की होगी कि यह सामान्य घटना आगे चलकर पुर्तगाल, फ्रांस, डच और अंत में अंग्रेजों के यहां आने और फिर सैकड़ों वर्षों तक भारत को अपना उपनिवेश बना लेने का सबब बनेगी?

कन्नूर के इस पथरीले तट पर आकर टकराती समुद्री लहरों को देखते हुए मैं यही सोच रहा हूं कि क्या हम अब भी यह समझ पाए हैं कि हम जिस सूचना युग में प्रवेश कर रहे हैं वहां पर इंस्टैंट मेसेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन मूवी हमारे लिए कौन सी चुनौतियां छिपाए हुए हैं?

किंतु-परंतु में उलझी भाजपा दिल्ली की राजनीति में

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

> भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर येन केन प्रकारेण चुनाव पहले कराया जाए तभी कुछ उम्मीद जग सकती है लेकिन चुनाव निर्धारित अवधि से पहले कराना आसान नहीं होगा

दिल्ली में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पसोपेश में है। इसकी वजह भी साफ है। अगले साल जनवरी-फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर भाजपा अपनी संभावनाएं टटोलने में जुट गई है। भाजपा के एक नेता ने कहा, 'मौजूदा समय अहम है। तत्काल चुनाव होगा तभी हमें फायदा होगा।' दिल्ली विधानसभा का 2015 का चुनाव 5 फरवरी तक पूरा हो गया था और नतीजे 10 फरवरी तक आ गए थे। चुनाव में प्रचंड जीत के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, जबकि दो प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं।

इस बार भाजपा को सभी समीकरण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। पार्टी स्वीकार कर रही है कि केजरीवाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता में लौटने की अच्छी संभावनाएं हैं। भाजपा को लगता है कि अगर येन केन प्रकारेण चुनाव पहले कराया जाए तभी कुछ उम्मीद जग सकती है।

चुनाव निर्धारित अवधि से पहले कराना आसान नहीं होगा और बिना साम-दाम दंड-भेद के यह मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और इस समय 65 विधायक हैं। इनमें आप से इस्तीफा देने वालीं अलका लांबा और पार्टी के अन्य विधायक भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ कानूनी मामले चल रहे हैं। भाजपा के चार विधायक हैं, जबकि कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। शेष सभी आप के हैं। सन 2015 में आप को 67 सीटें मिली थीं। हालांकि अब इसके कई विधायक सदस्यता के अयोग्य हो चुके हैं। राज्य सरकार को तब भी कोई खतरा नहीं है और आप स्वयं विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश करे तभी यह निर्धारित अवधि से पहले हो सकता है।

कुछ देर के लिए मान लें कि भाजपा की इच्छा के हिसाब से दिल्ली विधानसभा का चुनाव निर्धारित समय से पहले होता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? भाजपा का मानना है कि शीला दीक्षित के निधन के बाद केवल कांग्रेस को ही नहीं बल्कि भाजपा को भी नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 23 प्रतिशत मत मिले थे। दिल्ली की सात में से पांच लोकसभा सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। भाजपा को 56.5 प्रतिशत मत मिले थे और वह सभी सीटें जीत गई थीं।

यही वजह है कि भाजपा दिल्ली में समय से पहले चुनाव चाहती है। पार्टी को लगता है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का लाभ तभी मिलेगा जब राज्य विधानसभा का चुनाव कुछ हफ्तों के अंदर हो जाए। भाजपा नेता ने कहा, 'एक बार देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर महसूस किया जाने लगा तो अनुच्छेद 370 हटाने से संभावित लाभ असरदार नहीं रह जाएगा। ऐसे में हमारे लिए मजबूत दावेदारी पेश करना आसान नहीं रह जाएगा।' भाजपा के नजरिये से शीला दीक्षित की मौजूदगी से कांग्रेस का मत प्रतिशत 3 से 4 प्रतिशत और कम हो जाता। भाजपा की नजरों में 18 प्रतिशत मत प्रतिशत के साथ कांग्रेस ने आप के मतों में सेंध लगाई होगी, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिला होगा।

भाजपा नेता ने कहा, 'हालांकि कांग्रेस औंधे मुंह गिरती है और आप और मजबूत होती है तो उस हालत में हमारे लिए मुश्किल होगी।' जिस तरह अर्थव्यवस्था में सुस्ती के पीछे संरचनात्मक और आर्थिक हालात से जुड़े पहलू जिम्मेदार हैं, उसी तरह दिल्ली में भाजपा का पत्ता कटने के पीछे भी कुछ ऐसे ही कारण हैं। पहले भाजपा ताकतवर पंजाबी मत अपने पाले में करने के लिए विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना और केदार नाथ साहनी पर निर्भर रहती थी। इसके बाद दिल्ली में पार्टी को वैश्य समुदाय का सहारा मिला गया। विजय गोयल इस समुदाय के जाने-माने चेहरे थे और उनके बाद हर्षवर्द्धन (मौजूदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री) ने भी पार्टी को मजबूती दी। 2013 में हर्षवर्द्धन के मुख्यमंत्री बनने की पूरी गुंजाइश थी क्योंकि तब भाजपा को 32 सीटें मिली थीं और बहुमत से मात्र चार सीटें दूर थीं। 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री खुराना ने जैन हवाला डायरी में आडवाणी का नाम आने के बाद उनके प्रति समर्थन जताते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय हर्षवर्द्धन दिल्ली में भाजपा का मुख्य चेहरा थे। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने उन्हें आगे भी बढ़ाने की कोशिश की थी।

अब हर्षवर्द्धन कैबिनेट मंत्री हैं और शायद इस पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। गोयल सभी के विश्वासभाजक नहीं हैं। ऐसे में सबकी नजरें मनोज तिवारी पर हैं, जो दिल्ली में बिहार और उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती आबादी का चेहरा बन गए हैं। तिवारी इस समय सांसद और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं। अगर दिल्ली में पार्टी का आंतरिक चुनाव नहीं होता है और वह अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं और विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि वह भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।

हालांकि इस सभी किंतु-परंतु की नौबत तब आएगी जब कांग्रेस को कम से कम 15 से 18 प्रतिशत मत प्राप्त होगा। उस स्थिति में भाजपा को रोकना नामुमकिन होगा। हालांकि कांग्रेस का मत प्रतिशत नीचे गया (मान लें 8 प्रतिशत) और भाजपा और आप में सीधा मुकाबला हुआ तो क्या होगा यह कह पाना मुश्किल है। भाजपा को इसी बात का डर सबसे अधिक सता रहा है।

कानाफूसी

गजब संयोग

अंदाजा लगाइए कि बीती आधी सदी में देश के प्रधानमंत्रियों के अधीन काम करने वाले 13 प्रधान सचिवों में से सबसे अधिक किस जाति नाम वाले थे। इन सभी में मिश्रा जाति के सचिवों का वर्चस्व रहा है। अब तक चार ऐसे लोग प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं जिनकी जाति मिश्रा है। यह तादाद इस अवधि के कुल प्रधान सचिवों की तकरीबन एक तिहाई है। यह बात सही है कि इनमें से एक नृपेंद्र मिश्रा अपने नाम के अंग्रेजी हिज्जे अलग लिखते थे लेकिन उनके अलावा भी इस पद पर तीन ऐसे लोग रहे हैं जिनके नाम क्रमश: एस के मिश्रा (प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में), ब्रजेश मिश्र (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में) और पी के मिश्रा हैं। पी के मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा प्रधान सचिव हैं।

कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष?

मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा यह लाख टके का सवाल है। फिलहाल मुख्यमंत्री कमलनाथ इस पद पर हैं। वह पद छोड़ने वाले हैं और इसके कई दावेदार पहले ही सामने आ चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने चयन की दुविधा बनी हुई है। पिछले दिनों पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने एक ट्वीट करके अपनी पीड़ा प्रकट की। उन्होंने लिखा कि वह 15 वर्ष तक कर्मठ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक भ्रष्ट व्यवस्था से जूझते रहे, अपनी जान को जोखिम में डाला लेकिन बीते आठ महीनों में जो कुछ हुआ है उससे वह क्षुब्ध हैं। इसके पश्चात सोनिया गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया और उनसे करीब 20 मिनट तक बातचीत की। इसके बाद अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। यादव चार वर्ष तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव से महज छह महीने पहले पार्टी ने उनकी जगह कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था।

आपका पक्ष

स्वास्थ्य बीमा आज की जरूरत

वर्तमान समय की महत्त्वपूर्ण जरूरतों में से एक स्वास्थ्य बीमा को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दुर्घटना या बीमारियों की वजह से अचानक उत्पन्न किसी वित्तीय आपात स्थिति से निपटने में यह बीमा कारगर होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 70 प्रतिशत लोगों ने कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं लिया है। ऐसे लोग आपात चिकित्सा स्थिति में भुगतान के लिए अपनी बचत पर निर्भर रहते हैं। इससे उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा चिकित्सा में व्यय हो जाता है। आधुनिक जीवनशैली के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर तो पड़ ही रहा है। महंगाई के कारण इलाज का खर्च भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य बीमा की शर्तों को भी सामान्य और सरल बनाने की जरूरत है। बीमा के प्रति लोगों की यह अवधारणा है कि इसका क्लेम आसानी से नहीं मिलता है जिससे लोग बीमा लेने से कतराते हैं। हालांकि अब लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ लेने लगे हैं। लेकिन जो सक्षम हैं उन्हें स्वयं बीमा कराना चाहिए। मोटर वाहन के लिए बीमा अनिवार्य शर्त है लेकिन स्वास्थ्य बीमा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अत: जिस तरीके से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना शुरू कर नाममात्र के प्रीमियम पर लोगों का बीमा कराया जा रहा है उसी तरह सस्ते स्वास्थ्य बीमा योजना की जरूरत है।

जीतेंद्र साहू, शहडोल

> **स्वास्थ्य बीमा की शर्तों को सामान्य और सरल बनाने की जरूरत है**

विश्व शांति दिवस और भारत

हर साल 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श माना जाता है। पूरे विश्व में शांति कायम करना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्ष रोकने तथा शांति की संस्कृति विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है। विश्व में शांति का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और खेल-जगत की विश्वविख्यात हस्तियों को शांतिदूत नियुक्त किया है। लेकिन विश्व में अशांति का माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत अछूता नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से भारत में हिंसा फैलाने की फिराक में रहता है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत 163 देशों में से 141वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2018 में भारत का स्थान 136वां था। सबसे अशांत देश के रूप में इस बार अफगानिस्तान का नाम आया है। पिछले साल सीरिया को सबसे अशांत देश बताया गया था। विश्व शांति दिवस के अवसर पर हर देश में सफेद कबूतरों को उड़ाया जाता है। यह परंपरा काफी पुरानी है। कबूतर अपने संदेश में भाईचारे का संदेश देता है।

अजय प्रताप तिवारी, गोंडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।